महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहूंगा इसके साथ-साथ कि टेलीफोन, टेलेक्स और फैक्स का कनेक्शन, पर्सनल यूज के लिए होता है--यहां आफिशियल पर्पज के लिए एक टेलीफोन एक सौ आर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं, एक टेलेक्स सौ आर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं, एक फैक्स के कनेक्शन का हजारों लोग उपयोग कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है और कौन इसके लिए बना रहा है? इसको देखने की जरूरत है और यह क्या सरकार का रेवेन्यू बिठाने दफ्तरों से किसी मुख्य-मुख्य अधिकारियों की जेब में तो नहीं जा रहा है? इस पर कोई खोजबीन की गई है क्या, मैं यह जवाब जानना चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह: माननीय यह नहीं कहा गया है कि कोरियर सर्विस नहीं चलाई जा रही है, कोरियर सर्विस चल रही है और इसके बारे में समय-समय पर जब कोई बात होती है तो जानकारी भी करते हैं।

माननीय, एक बार हमने डिपार्टमेंट के द्वारा प्रयास किया था, अनौपचारिक रूप से देखा गया कि देश में लगभग 150 कोरियर सर्विस चल रही हैं, लेकिन उनका लाईसेंस जारी करने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। उस पर देखा जा रहा है कि उस पर क्या किया जाए। जहां तक पत्र ले जाने का, जैसा माननीय अहलुवालिया जी ने कहा, उसके बारे में हमने कहा है कि इसका एक अमेंडमेंट हम कर रहे हैं। उसमें यह प्रोवीजन कर रहे हैं कि कम से कम तीन साल की सजा हो और पेनल्टी भी बढ़ा रहे हैं। तो जब यह हो जाएगा, तो माननीय, जो यह शिकायत आती है, वह शिकायत आने की संभावना नहीं रह जाएगी।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: सभापति महोदय, लिफाफों के अंदर डालर की करेंसी जा रही है, स्टर्लिंग जा रहे हैं या पाऊंड जा रहे हैं, क्या यह कभी खोज की गई है? इंटरनेशनल रेप्यूट की कोलिशन सर्विसेज हिंदुस्तान में चल रही हैं।

मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस सबजैक्ट पर आधे घंटे की डिस्कशन होनी चाहिए और इस पर हिम्मत देकर रहीं-सहीं स्टेटमेंट के साथ गवर्नमेंट आए।

श्री सभापति: वह पूरे प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: आप हाफ-एन-आवर डिसकशन की बात पर विचार करें।

श्री सभापति: आप उसके लिए लिख कर दीजिए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: ठीक है, उसके लिए हम लिख कर देंगे।

Criteria for Opening of Rural Post Office

*8 SHRIMATI RATAN KUMARI:
DR. RATNAKAR PANDEY†

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what are the criteria laid down for opening of post offices in rural areas;

(b) what is the number of eligible villages in the country where post offices are yet to be opened; and

(c) what is the target fixed for opening of such post offices in 1989-90?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Ratnakar Pandey.

Statement

(a) The following criteria are laid down for opening of post offices in rural areas :

Extra-departmental branch post offices (EDBOs):

(i) A group of villages constituting a gram panchayat will be eligible for a post office provided that (a) the aggregate population of the group of villages is not less than 3000 in normal rural areas and 1500 in hilly, backward and tribal areas and (b) there is no other post office within the group.

(ii) The post office will normally be opened at the headquarter village of the gram panchayat. If such a village falls within 3 kms. of an existing post office, the post office may be opened in another suitable village within the same gram panchayat which fulfils the distance condition.

(iii) The 3 kms. restriction can be relaxed in hilly areas in cases where such relaxation is warranted by special circumstances.

(iv) The minimum anticipated revenue will be 33. 1/3% of the cost in normal rural areas and 15% of the cost in hilly, tribal and backward areas.

Classification of hilly, backward and tribal areas will be made according to the following criteria:

Hilly areas:

(i) "Special Category States", namely, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Sikkim, Arunachal Pradesh and Mizoram.

(ii) Districts/Blocks/Talukas in other States or Union Territories identified by the Planning Commission as hill areas for purposes of Hill Areas Development Programme (HADP).

Tribal areas:

(i) States/Union Territories which have tribal population exceeding 50% of the total population namely, Arunachal Pradesh, Dadra and Nagar Haveli, Lakshadweep, Nagaland, Meghalaya and Mizoram.

(ii) Districts/B.ocks/Sub Divisions/ Tehsils/villages in other States/ Union Territories Identified Tribal Development Programme (ITDP).

Backward areas:

(i) Areas identified by the State Government for implementation of the Backward Area Development Programme under the Seventh Plan (Village and Small Industries sector).

In view of the continuing ban on creation of posts, proposals for opening of new branch offices will be submitted by the Department of Posts to the Ministry of Finance for grant of exemption.

Departmental Sub Post Offices (DSOs): Departmental sub-post offices may be opened under the Plan Scheme of 'Expansion of Postal Network' subject to the following provisions:

(i) The new scheme will cover departmental sub-offices to be set up in project areas/new industrial estates/townships and other similar developments which have come up in new areas in pursuance of the Plan Schemes in State/Central/Joint Sectors. In other words, the concept of Postal sector plan will be enlarged to cover the communications infrastructure required for the over-all National Plan.

(ii) The posts required for the opening of departmental sub-offices under this scheme will be created with the approval of Secretary in the Ministry of Finance (Department of Expenditure).

(iii) Only proposals in which the minimum anticipated workload as per Marathe Time Test (excluding sub accounts & accounts work) is 5 hours can be considered.

(iv) The permissible limits of loss of Rs. 2400 (in normal rural areas) and Rs. 4800 (in hilly, backward and tribal areas), will be applicable to departmental sub offices set up in hilly/backward/tribal areas. Proposals in which the anticipated loss is likely to exceed these limits will be dealt with under the scheme of Non-Returnable Contributions (NRC).

(b) and (c) Eligibility is not determined in respect of individual villages but with reference to groups of villages preferably a group constituting a gram panchayat or other similar panchayati raj institution with a combined population of 3000 or in the case of hilly, backward and tribal areas 1500. Further, the population criterion is applied in conjunction with other related factors such as distance from the nearest post office and anticipated postal income.

The Seventh Plan assessment was that based on the prescribed criteria up to 31-3-1990, there was scope and need for about 6,000 new post offices in the rural areas over and above the figure of 1,29,589, rural post offices reached by 31-3-1985. Out of this, assessed figure by 31-3-1989, 3561 post offices have either been already opened or sanctioned are likely to be opened shortly. The target for 1989-90 is expected to be of the order of 2,500 new post offices.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी, एस्टिमेट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 4 अप्रैल, 1989 को लोक सभा पटल पर रखी है और उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में डाक-घर खोलने के बारे में डाक-तार मंत्रालय के रवैये की निंदा, भर्त्सना और आलोचना की गई है। यदि ऐसा है तो एस्टिमेट्स कमेटी की इसके बारे में क्या सिफारिशें हैं और सरकार उन पर क्या कार्यवाही करना चाहती हैं—यह मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं?

श्री सभापति : एस्टिमेट्स कमेटी की सिफारिशें तो आप स्वयं पढ़ सकते हैं। वह तो आपके सामने आती हैं। आप क्या करने जा रहे हैं, वह प्रश्न है। आप उस पर गौर करेंगे।

संचार मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह) : मान्यवर, यह देखेंगे कि जहां तक कोई व्यवस्था खराब है, या ठीक नहीं है, उसको ठीक करेंगे, लेकिन एस्टिमेट्स कमेटी की कोई बात यहां पर नहीं आती है।

श्री सभापति : आप एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट को पूरा वेट देंगे।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी, एस्टिमेट्स कमेटी ने जो सदन के सामने अपनी रिपोर्ट रखी है, उसमें लिखा है कि सातवीं पंच वर्षीय योजना में अठारह हजार पोस्ट-आफिस खोलने का लक्ष्य था, लेकिन बारह हजार प्रस्तावित किये गये और 1990 तक माननीय मंत्री जी ने बताया कि 6661, जो छह हजार का लक्ष्य था, वह पूरा हो जाएगा, और जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, उसमें दो जगह यह देखने में आया है पेज 2 पर कि पिछड़े क्षेत्र में पोस्ट-आफिस खोलने के लिए कि सातवीं पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत तथा लघु उद्योग क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र, विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्र पदों के सृजन पर लगी पाबंदी के कारण नए शाखा डाकघर खोलने संबंधी प्रस्तावों को छूट दिए जाने के लिए डाक विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह आपके विभागीय उप डाकघर के संबंध में भी है कि इस स्कीम के अंतर्गत विभागीय डाकघर खोलने के लिए अपेक्षित पद सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की अनुमति से बनाए जायेंगे, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय को कितने के लिए

हमारे डाक तार मंत्रालय ने लिखा है और उसमें क्या प्रगति हुई है और अब तक जो प्रस्ताव हमारे डाक तार मंत्रालय ने रखा है उसका कोई निष्कर्ष वित्त मंत्रालय के सहयोग से निकल सकेगा क्योंकि बिना वित्त मंत्रालय की स्वीकृति के कोई काम आगे बढ़ नहीं पाता है इसलिए उसमें क्या प्रगति हुई है, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ?

श्री बीर बहादुर सिंह : मान्यवर, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना में डाकघर खोलने का जो प्रस्ताव था उसमें कुल 6 हजार डाकघर खोलने थे, जिसमें से 2600 से ज्यादा 3500 के करीब खुल चुके हैं और बाकी करीब 2500 इस साल 1989-90 में खोले जायेंगे। इस प्रकार यह 6000 का जो लक्ष्य है इसे हम पूरा करेंगे। जहां तक और भी धन की आवश्यकता है, मान्यवर, जितनी धन की आवश्यकता होती है उसका वित्त विभाग से मांग किया है। जितना बिल भेजा था उसका किया गया लेकिन जो इस साल होना है जो 6000 का लक्ष्य है उसको पूरा करने का प्रावधान है।

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर में पोस्ट आफिस खोलने के संबंध में जो क्राइटेरिया बताया है उसके अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र के ग्राम समूहों की संख्या तीन हजार निर्धारित की है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जैसे मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम समूहों की संख्या तीन हजार नहीं हो पाती है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक पोस्ट आफिस हो? दूसरा, जो उन्होंने क्राइटीरिया दिखाया है वह यह है कि जिन गांवों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है ट्राइबल क्षेत्र के क्या वह सुनिश्चित करेंगे कि जहां जिस ग्राम पंचायत में एक पोस्ट आफिस खुल गया है लेकिन उसी ग्राम पंचायत में निर्धारित तीन किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत यदि दूसरा कोई ऐसा गांव है जहां कि ट्राइबल लोगों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है क्या वह उस गांव में दूसरा कोई पोस्ट आफिस खोले जाने संबंधी निर्णय लेने जा रहे हैं ?

श्री बीर बहादुर सिंह : मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम भी है आज तक जो हमारे देश में पोस्ट आफिस खुले हैं एक लाख 44 हजार से ज्यादा खोले जा चुके हैं और जो इस बक्त मांग है उसको देखते हुए अगर हम करते हैं जैसा कि आप चाहते हैं कि हर गांव में खोले जायें तो 6 लाख के करीब गांव आते हैं, तो इतने अधिक गांवों में पोस्ट आफिस खोलना, मान्यवर, लगता है कि यह बहुत कठिन है लेकिन यह प्रयास किया जा रहा है कि तीन हजार की आबादी, जहां सामान्य तीन हजार की आबादी हो और जो ट्राइबल एरिया है, पर्वतीय क्षेत्र है, हिल्स एरिया है वहां पर डेढ़ हजार आबादी में भी पोस्ट आफिस खोल देते हैं यह सुविधा हम ऐसे एरिया में दिए हैं जहां पर पोस्ट आफिस नहीं खोले जाते थे ऐसे एरिया में खोले जा रहे हैं। अब हर गांव में खोलें तो काफी बड़ी संख्या हो जायेगी और जो हमारे पास धन है वह देखते हुए जितना माननीय सदस्य चाहते हैं उतना तो नहीं होगा लेकिन प्रयास किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाए।

श्री सुरेश पचौरी : माननीय मंत्री जी, मैंने आग्रह यह किया था कि क्या वह यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत कम से कम एक पोस्ट आफिस हो ? मैंने प्रत्येक गांव में नहीं बोला।

श्री बीर बहादुर सिंह : अभी इतना संभव नहीं हो सकता।

SHRI BASUDEB MOHAPATRA: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the Government has taken a policy decision to open branch offices in G. P. headquarters. That means gram panchayat headquarters. If so, what is the

number of post offices opened so far in G.P. headquarters all over the country, and how many G.P. headquarters have been left out? I am interested in knowing about the G.P. headquarters.

श्री बीर बहादुर सिंह : मान्यवर, ग्राम पंचायत यूनिट्स की जो संख्या है . . .

श्री सभापति : वह डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स के बारे में पूछ रहे हैं ।

SHRI BASUDEB MOHAPATRA: Gram Panchayat Headquarters, Sir.

श्री बीर बहादुर सिंह : वह काफी जगह पर खोले जा चुके हैं । लगभग 28 हजार 9 सौ खोले जा चुके हैं।

SHRI BASUDEB MOHAPATRA: Sir, my question has not been answered. My question was in how many G.P. Headquarters post offices have been opened so far and how many headquarters have been left out. I want to know that.

MR. CHAIRMAN : Since the criteria for Panchayat changes, he cannot give you an up-to-date answer. He will have to get the number of headquarters of the different Panchayats in different States. Then only he can answer. He can tell you what he has done. You know the State Governments often change the headquarters of Panchayats and areas of Panchayats. Next question.

*9. [*The questioners (Shri Dhuleshwar Meena and Dr. (Shrimati) Sarojini Mahishi) were absent. For answer* vide *Cols.* 40-41 infra]

STD Lock Facilities

*10. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government propose to provide dynamic STD lock facilities in digital electronic exchanges in which telephone subscribers having STD bar will be given a secret code number with which they would be able to open or close STD at their own will and the code would not even be known to the exchange people as reported in the Hindustan Times dated the 25th February, 1989;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what are the names of the exchanges where these facilities are likely to be provided, State-wise; and

(d) by when such exchanges propose to start functioning?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BIR BAHADUR SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. Experiments are being conducted on a system called "Subscriber controlled STD" in E-10B type digital electronic exchanges.

(b) Under the system, STD/ISD calls facility can be activated/deactivated by subscriber himself by dialling a code chosen and known to him only.

(c) and (d) This introduction will depend upon the success of the experiment and the facility will be provided to all E-10B exchanges only.

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : चेयरमैन साहब, यह जो एक्सपेरीमेंट किया जा रहा है इसका मैं स्वागत करता हूं । अगर यह सक्सेसफुल हो गया तो इससे डिपार्टमैंट के अंदर जो करप्शन चल रहा है, वह एलिमिनेट हो जाएगा ।

चेयरमैन साहब, मैं अपनी एक मिसाल देना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि